ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 194-196

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

भारतीय ग्रामीण समाज में भारत अभियान की चुनौतियॉं

डॉ0 ज्योति गुप्ता

असि0 प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष– समाजशास्त्र विभाग, मदन मोहन मालवीय पी0 जी0 कालेज, कालाकंकर– प्रतापगढ़ (उ0प्र0) भारत

Received-18.06.2022, Revised-23.06.2022, Accepted-27.06.2022 E-mail: jyotigupta2088@gmail.com

सारांशः– *मनुष्य की यह प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि वह स्वच्छ रहे। स्वच्छ केवल अच्छे स्वास्थ्य का ही नही, बल्कि आत्मसम्मान का भी मूलाधार है और इसका मानव जीवन से गहरा सम्बन्ध है। इतिहास हमें बताता है कि मूलभूत स्वच्छता में किया गया निवेश गरीबी , बीमारी तथा असमय होने वाली मृत्यु से छुटकारा दिलाने में लोगो की मदद कर सकता है। भारत में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में 1954 में शुरू किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य प्राथमिक रूप से ग्रामीण लोगो के जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा महिलाओ के सम्मान में वृद्धि करना था। 1999 से "सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान " के अन्तर्गत "मांग जनित " दृष्टिकोण ने ग्रामीण लोगो बीच जागरूकता तथा स्वच्छता सुविधाओ के लिए मांग सृजन में वृद्धि करना। पहले के सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के बदले "निर्मल भारत अभियान 01/04/2012 से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छता कवरेज की गति तेज करना था।*

सर्वव्यापी स्वच्छता पर ध्यान संकन्द्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की है। जिसका उद्देश्य 2019 तक स्वच्छ भारत की स्थिति प्राप्त करना तथा ग्राम पंचायतो को खुले में शौच से मुक्त, स्वच्छ एंव साफ–सुथरा बनाना है। वर्तमान शोध पत्र में भारतीय ग्रामीण समाज में स्वच्छता के विभिन्न आयामो व चुनौतियो पर प्रकाश ड़ाला गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में स्वच्छ भारत अभियान के सम्बन्ध में स्वच्छ भारत अभियान एंव इसके विभिन्न आयामों के सम्बन्ध, भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में आने वाली बाधाओ का अध्ययन किया गया है। इस शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ो का प्रयोग करते हुए स्वच्छ भारत अभियान के कियान्वयन तथा उसके ग्रामीण समाज पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

कुंजीभूत शब्द– प्रव्रजन, उत्प्रवास, अप्रवास, प्रकार्य, आधुनिकीकरण, भावनात्मक तटस्थता, सैमिटेंस, पुश–पुल थ्योरी।

मनुष्य की यह प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि वह स्वच्छ रहे। स्वच्छता केवल अच्छे स्वास्थ्य का ही नही, बल्कि आत्मसम्मान का भी मूलाधार है और इसका मानव जीवन से गहरा सम्बन्ध है। स्वच्छता का अहसास भी जुड़ा होता है। इसके कारण मनुष्य में आत्मसम्मान का बोध होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की तरह ही स्वच्छता भी भारत में फैली गरीबी के विरूद्ध लड़ने में एक महत्वपूर्ण हथियार है। इतिहास हमें बताता है कि मूलभूत स्वच्छता में किया गया निवेश गरीबी, बीमारी तथा असमय होने वाली मृत्यु से छुटकारा दिलाने में लोगो की मदद कर सकता है। भारत में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्शीय योजना के रूप में 1954 में शुरू किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देष्य प्राथमिक रूप से ग्रामीण लोगो के जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा महिलाओ के सम्मान में वृद्धि करना था। 1999 से "सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान" के अन्तर्गत "मांग जनित" दृष्टिकोण ने ग्रामीण लोगो के बीच जागरूकता तथा स्वच्छता सुविधाओ के लिए मांग सृजन में वृद्धि करना। पहले के सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के बदले "निर्मल भारत अभियान" 01.04.2012 से शुरू किया गया। इसका उद्देष्य ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छता कवरेज की गति तेज करना था। सर्वव्यापी स्वच्छता पर ध्यान संकन्द्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की गई। जिसका उद्देष्य 2019 तक स्वच्छ भारत की स्थिति प्राप्त करना तथा ग्राम पंचायतो को खुले में शौच से मुक्त, स्वच्छ एंव साफ–सुथरा बनाना है।

स्वच्छ भारत अभियान के उद्देष्य–

(क) स्वच्छता, साफ–सफाई और खुले में शौच प्रथा समाप्त करने को बढावा देकर ग्रामीण क्षेत्रो में लोगो के सामान्य जीवन को सुधारना।

(ख) जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता और आदतें अपनाकर समुदायो और पंचायती राज संस्थाओ को प्रेरित करना।

(ग) पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित एंव स्थायी स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी और संगत प्रौद्योगिकियों को बढावा देना।

शौचालय निर्माण से सम्बंधित– समूचे देश में व्याप्त होने और बहुत उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद भी ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चुनौतियों से अछूता नहीं हैं। सामाजिक–आर्थिक स्थितयो तथा प्रशासनिक संरचनाओ में राज्यवार

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

भिन्नता नें कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जटिलताओ को बढाया हैं। भारत सरकार ने 2019 में भारत को 100 प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त घोशित किया तथा 100 प्रतिशत शौचालय निर्माण का दावा किया। परन्तु नैशनल सैम्पल सर्वे आफिस के दिसम्बर 2018 के सर्वेक्षण से पता चला कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रो में करीब 71.3 प्रतिशत परिवारों को ही शौचालय उपलब्ध हो पाया हैं। राज्य स्तर पर एन0एस0ओ0 के सर्वेक्षण से पता चला कि झारखण्ड में 42,तमिलनाडू 37, राजस्थान 34 और गुजरात में एक चौथाई घरो के पास शौचालय तक पहुंच नहीं है। जबकी इन चार राज्यो को 100 प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। बहुत पुरानी आदत होने के कारण, यदि घरो में शौचालय सुविधाओ को स्थापित भी कर लिया जाए तो भी उसका 100 प्रतिशत जल उपलब्धता तथा शौचालय गुणवत्ता बनी रहे एक बड़ी चुनौति है। कैरवन मैगजिन के सर्वेक्षण पता चला कि जिन शौचालयो का निर्माण हो चुका है उनमें अधिकतर की स्थिति खराब है और उसका उपयोग वस्तुओ को रखने में किया जाता है।

शौचालय उपयोग से सम्बंधित– ग्रामिण क्षेत्रो में शौचालय इस्तेमाल नहीं करने के कारण–

1. पानी की किल्लत 2. शौचालय में बैठने की स्थिति नहीं होना 3. बदबू आना 4. शौचालय में अंधेरा होना और 5. ताजी हवा नहीं आना

केंद्र में प्रधानमंत्री के कार्यालय में देश भर में कितने शौचालय बने इसके आंकडे हैं, लेकिन इसका कोई आंकडा नहीं कि बनाए गए शौचालय को कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। साफ है कि शौचालय बनाने का ये मतलब कतई नहीं माना जाए कि उन शौचालयो का इस्तेमाल हो रहा हैं। नैशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के दिसम्बर 2018 के आंकडो के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रो में जिन 71.3 प्रतिशत घरो में शौचालय थे उनमें से 3.5 प्रतिशत पारिवारिक सदस्यों ने शौचालय का कभी उपयोग कभी नहीं किया और 4.5 प्रतिशत परिवारो ने दर्ज किया कि उपयोग करने वाले शौचालय के आसपास या शौचालय में जल उपलब्ध नहीं था।

गड्ढे लबालब भर जाने, शौचालय में अंधेरा होना, हवा की आवाजाही नहीं होने, बदबू आने, पानी नहीं होने, जैसे कारणो से कुछ लाभार्थी शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर रहे है। हो सकता हैं कि जिन शौचालय का प्रयोग किया जा रहा है, इन्ही कारणो से आगे चलकर उनका प्रयोग न किया जाये। जो इस अभियान के लिए बाधा उत्पन्न करता हैं।

प्रौद्योगिकी से सम्बंधित– शौचालय निर्माण में प्रौद्योगिकी संबंधी दोश शौचालय के उपयोग पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। प्रौद्योगिकी ज्ञान अल्पता के कारण शौचालय उपयोग संबंधी समस्या खड़ी हो गई है। कुछ पंचायतो मे की गई प्राथमिक शोध में सामने आया कि 31 प्रतिशत शौचालय उपयोग में न होने के लिए घटिया या अधूरा शौचालय निर्माण उत्तरदायी है। इसी अध्ययन ने दर्शाया है कि पैन और निकासी पाइपो के बंद हो जाने के कारण 26 प्रतिशत घरेलू शौचालय उपयोग उपयोग नहीं हो रहे हैं। सरकार ने शौचालय का निर्माण करवा दिया परन्तु सोख्ता पिट का निर्माण अधिक्तर शौचालय में नहीं हुआ है। जिसके कारण अस्वच्छता फैल रही है और शौचालय उपयोग में कमी आ रही हैं।

सेप्टिक टैंको से जुडी कुछ अन्य समस्याओ भी है भारतीय मानक ब्यूरो के निर्देश के अनुसार 2000 लीटर से अधिक क्षमता वाले सेप्टिक टैंक के लिए कम से कम दो चैम्बर होने चाहिए, जिनके बीच में दीवार हो लेकिन ग्रामीण क्षेत्रो में इन मानको का पालन नहीं किया जा रहा हैं। जिसके कारण एक ही चैम्बर वाले टैंक बनाये जाते है, जिनके पाइप से मलबा निकलता रहता है जिसके कारण निकले मलबे का सुरक्षित निस्तारण न होने के कारण अस्वच्छता बनी रहती है।

एन0जी0ओ0 और पंचायती राज संस्थाओ के बीच भूमिका संबंधी विरोध– स्वच्छ भारत अभियान में बड़े पैमाने पर सामाजिक गतिशीलत की जरूरत होती है जिससे ग्राम स्तर पर भी प्रमुख हिस्सेदारी की सहभागिता की आवश्यकता पड़ती है ऐसे मामले में पंचायती राज संस्थाओ की भूमिका सर्वोच्च बन जाती हैं। पंचायती राज संस्थाओ तथा एन0जी0ओ0 के साथ कार्य करने में बहुत ज्यादा अनिच्छा रही हैं। अधिकांश राज्यो में स्वच्छ भारत अभियान को अधिकारिक तौर पर या तो जिला पंचायतो द्वारा या जिला पंचायतो अध्यक्षता में जिला जल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। गैर सरकारी संगठनो का पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है। जिससे स्वच्छता का विकास नहीं हो पाया है। चाहे कागजो पर यह व्यवस्था ठीक दिखाई देती है, किंतु व्यावहारिक तौर पर यह अधिकांशतः उन राज्यो में गंभीर चुनौतियां पेश करती है जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस प्रवृत्ती के कारण कुछ संस्थागत संरचना में ऐसा व्यवहार बाधा उत्पन्न करता हैं।

एकीकरण एंव समन्वय की चुनौति– स्वच्छता प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रम में प्रयासो की एकसूत्रता के लिए की गई अच्छी शुरूआत के बावजूद राज्य, जिला व ग्राम स्तर पर बहुत सी प्रचालन संबंधी चुनौतियां है। यह उल्लेखनीय है कि शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की दो बड़ी परियोजनाओ– सर्व शिक्षा अभियान तथा मिडे डे मील को भारत सरकार की सभी सरकारी

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

विद्यालयों में लागू करने में शामिल हैं। चूंकि अधिकांश समय अध्यापक तथा शिक्षा कार्यक्रम अधिकारीगण उनके अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहते है, जिससे विद्यालयी स्वच्छता का अभाव पाया जाता है। जिन राज्यों व जिलों में, जहाँ प्रभावी एकसूत्रता का रूप नहीं ले पाई है, निम्न चुनौतियां दिखाई देती है–

1– प्रायः ऐसी शिकायते मिली है कि अध्यापक/अध्यापिकाएं शौचालय पर ताला लगाकर रखते है और कुंजी अपने उपयोग के लिए ही रखते है तथा बच्चो को इस्तेमाल नहीं करने देते है, जो स्कूल जलापूर्ति, स्वच्छता एंव साफ–सफाई की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यो में एक बडी बाधा है।

2–विद्यालयी स्तर के साथ–साथ अभिभावक–शिक्षक संघ के साथ भी बातचीत के अभाव में शौचालय का प्रचालन व रख–रखाव प्रभावित होता है। कभी–कभी अभिभावक और ग्राम समुदाय द्वारा बच्चो को शौचालय सफाई के कार्य में लगाए जाने का विरोध भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, तीन मंत्रालय ऐसे है जिनके बीच समन्वय रख पाना कठिन कार्य है जो तकनीकी तौर पर इस मिशन को निभा रहै है–

–पेयजल एंव स्वच्छता मंत्रालय

–ग्रामीण विकास मंत्रालय

–स्वच्छ विद्यालय अभियान जो मानव विकास मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। इन मंत्रालयो के समन्वय के अभाव में अभियान में रूकावट आ सकती है जो स्वच्छ भारत अभियान की सफलता को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष– पिछले कुछ वर्षों में भारत में ग्रामीण स्वच्छता अभियान में एक अच्छी शुरूआत की गई है। विगत कुछ वर्षों में किए गए बहुत से प्रयासो के बावजूद, 2012 में व्याप्त 40 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता प्रसार 2019 में बढकर मात्र 71 प्रतिशत तक ही बढा है, जो संकेत करता है कि मंजिल अब भी बहुत दूर है। यह केवल सतत् एंव सामूहिक प्रयासों के द्वारा ही पायी जा सकती हैं।यह अनिवार्य है कि न केवल विद्यमान संवेग को बनाए रखा जाए, बल्कि उसे आगे और तेज भी किया जाए। साथ ही लक्ष्यो तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट दृष्टि की भी जरूरत है। इसका आशय है कि कार्यक्रम के मुख्य निर्माण खण्डो पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जिसमें मुख्य हिस्सेदारों की क्षमता का निर्माण, सामाजिक गतिशीलता व जागरूकता पैदा करना, आपूर्ति श्रृंखला और विभिन्न संस्थागत संरचनाओं की भूमिका स्पष्ट करते उन्हें मजबूती प्रदान करना।

मानव प्रवृत्ति और व्यवहार को जब तक समय–समय पर सही न किया जाए, तो उसमें भी अधोमुख होने का प्राकृतिक स्वभाव होता है। किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता एक समयावधि के बाद प्रभावित होती है इसलिए यह जरूरी है कि कार्यक्रम में कड़ी निगरानी और उपयुक्त समाधान उपायों का नियमित रूप से उपयोग किया जाए। शौचालय के उपयोग संबंधी अनुवीक्षण तथा स्वास्थ्यकारी व्यवहारों को अपनाने पर संकेंद्रण करना अत्यावश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार, आलोक(2015), स्क्वेटिंग विद डिगनिटी, नई दिल्ली, सेज प्रकाशन।
2. वाघेला, अनिल(2015), स्वच्छता का समाजशास्त्र, दिल्ली, कल्पाज प्रकाशन।
3. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान पर दिशा निर्देश द्वारा पेयजल आपूर्ति विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली जनवरी 2004.
4. संपादकीय, कौन का प्रश्न, योजना. 2015,59(1):7.
5. ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)।
6. भारत में पेयजल, स्वच्छता, आरोग्यता एंव आवासीय स्थिति, जुलाई 2018–दिसम्बर 2018.
7. Jain D, Malaiya S, Jain A. Studied that impacts of Swach Bharat Abhiyan in India. International Journal of Humanities and Social Science Research.2016,2(10).ISSN:2455-2070;Impact Factor:RJIF 5.22.
8. www.jansatta.com/Tag/Smartvillage सितम्बर 17, 2015,जनसत्ता मुख्याI'B 18.
9. Website:- sbm.gov.in
10. Website:-mdws.gov.in

*****